नईदुनिया

बोलने के अधिकार और नए सांसदों को अवसर देने को लेकर सदन में हुई बहस

राज्यसभा में खड़गे और रिजिजू के बीच नोकझोंक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई।

खड़गे ने कहा कि सदन में कब और किस विषय पर बोलना है, यह उनका अधिकार है और इसके लिए उन्हें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों का सम्मान नहीं कर रहा है तथा गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग दोहराई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस अपने नए सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एक ही मुद्दे पर बार-बार चर्चा से सदन का समय व्यर्थ हो रहा है और नए सदस्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी कई बार बाधित हुई और अलग-अलग समय पर स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे। विपक्ष पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर उनसे सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है।

दादरी में थाने के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग

नईदुनिया ब्यूरो, भिवानी: हरियाणा के दादरी शहर में सिटी थाने के सामने गुरुवार को अंधाधुंध फायरिंग की घटना में स्कॉर्पियो सवार सात लोग घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन हमलावर बाइक पर पहुंचे और करीब 30 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार सभी लोग कोर्ट से पेशी के बाद लौट रहे थे और मामले की जांच गैंगवार के एंगल से की जा रही है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं, रोहित गोदारा गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाला एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बदले नियम, आरती के लिए तत्काल पास की सुविधा शुरू

बदलाव : अयोध्या स्थित श्रीराम दरबार के दर्शन के लिए पास व्यवस्था समाप्त

नईदुनिया ब्यूरो, अयोध्या: श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या स्थित राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब मंदिर की प्रथम मंजिल पर स्थित राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। अब मंदिर आने वाले श्रद्धालु रामलला के दर्शन के साथ राम दरबार सहित पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कर सकेंगे।

राम दरबार का निर्माण पिछले वर्ष जून में पूरा हुआ था। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने दर्शन के लिए पास व्यवस्था लागू की थी। लगभग एक वर्ष तक व्यवस्था का परीक्षण करने के बाद ट्रस्ट ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, रामलला के सुगम दर्शन के लिए पास व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। ट्रस्ट ने बताया कि सुगम पास अब केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे। पहले इन पासों को जारी करने का अधिकार ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के पास था। उनके इस्तीफे के बाद अब दो से तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, जो सुगम पास जारी करने की प्रक्रिया का संचालन करेगी।

ट्रस्ट ने रामलला की आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए तत्काल पास की सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा बिड़ला धर्मशाला के सामने स्थित यात्री सुविधा केंद्र से उपलब्ध होगी। रामलला की आरती के लिए 45 और राम दरबार की आरती के लिए 15 तत्काल पास निर्धारित किए गए हैं। मंदिर में प्रतिदिन तीन आरतियां आयोजित होती हैं। मंगला आरती सुबह 4 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे तथा शयन आरती रात 9 बजे होती है। मंगला और श्रृंगार आरती के तत्काल पास एक दिन पहले जारी किए जाएंगे, जबकि शयन आरती के पास उसी दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आरती दर्शन के लिए पहले से ऑनलाइन 100 पास जारी करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी।

ट्रस्ट ने दैनिक पास व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी है। फिलहाल नए दैनिक पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। पहले से जारी 2,743 दैनिक पासों का सत्यापन और पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह व्यवस्था उन संतों और स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई थी, जो प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं।

ट्रस्ट के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को अधिक सुगम, व्यवस्थित और पारदर्शी दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच दर्शन और आरती की व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित की जा सके।

अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं : ट्रम्प

- राष्ट्रपति बोले, रक्षा उत्पादन तेज गति से जारी, गोपनीय जानकारी लीक करने वालों को दी कड़ी चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आवश्यकता के अनुसार नए हथियारों का उत्पादन भी तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे अधिक नए उत्पादन संयंत्र और फैक्ट्रियां स्थापित कर रही हैं, जिससे रक्षा क्षमता लगातार मजबूत हो रही है।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं लीक करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उन्हें लंबी अवधि के कारावास का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका संकेत किस विशेष गोपनीय जानकारी के लीक होने की ओर था।

हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका के पास लंबी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों, विशेषकर थाड और एटैकम्स से जुड़े हथियारों का भंडार तेजी से घट रहा है। ट्रम्प का यह बयान इन्हीं रिपोर्टों के बीच सामने आया है।

इस बीच पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए नए समुद्री मार्ग की रूपरेखा पर ओमान के साथ सहमति बनी है और दोनों देश जल्द इसकी संयुक्त घोषणा कर सकते हैं।

ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है और अगले 48 घंटे में संभावित समझौते की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान के साथ सहमति बनने के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता और क्षेत्र में सैन्य तनाव बना रहने पर सुरक्षा जोखिम भी जारी रहेंगे।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली के अधिकांश इंटरसेप्टर और पैट्रियट प्रणाली के बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर का उपयोग किया है।

पाकिस्तान की राजनीति में मोहसिन नकवी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा

इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान की राजनीति में मोहसिन नकवी की बढ़ती सक्रियता और प्रभाव को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाल के घटनाक्रमों के बीच उन्हें देश की सत्ता व्यवस्था में तेजी से उभरते प्रभावशाली चेहरों में माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों में उनकी भूमिका लगातार बढ़ने से पाकिस्तान के पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार मोहसिन नकवी ने पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसी कारण उन्हें पाकिस्तान की सत्ता संरचना में प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाने लगा है। राजनीतिक हलकों में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं और अटकलें भी सामने आ रही हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में सेना, सरकार और राजनीतिक दलों के बीच बदलते समीकरणों के दौर में मोहसिन नकवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। उनके निर्णयों और सक्रियता का असर कई राजनीतिक घटनाक्रमों पर दिखाई दे रहा है।

वहीं, कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों में सत्ता के विभिन्न केंद्रों के बीच संतुलन लगातार बदल रहा है। ऐसे में मोहसिन नकवी का बढ़ता प्रभाव भविष्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है।

सूर्य की सतह पर पहली बार दिखे चुंबकीय भंवर

- 'आग के बवंडर' जैसे दिखाई देने वाले सूक्ष्म भंवरों से सौर तूफानों के अध्ययन को मिलेगी नई दिशा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य की सतह की अत्यंत उच्च रिजॉल्यूशन तस्वीरों में छोटे-छोटे चुंबकीय भंवरों का अवलोकन किया है। इन संरचनाओं को देखने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की सतह पर होने वाली जटिल गतिविधियों और सौर तूफानों की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। इन भंवरों का स्वरूप आग के घूमते बवंडरों जैसा दिखाई देता है।

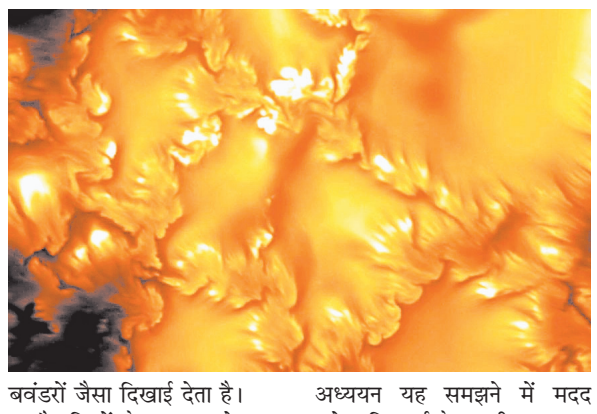

वैज्ञानिकों के अनुसार ये सूक्ष्म चुंबकीय भंवर सूर्य की सतह पर ऊर्जा और प्लाज्मा के प्रवाह से जुड़े हैं। इनकी गतिविधियों का अध्ययन यह समझने में मदद करेगा कि सूर्य के बाहरी वातावरण में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है और सौर तूफानों जैसी घटनाएं कैसे विकसित होती हैं। नई तस्वीरों में सूर्य की सतह के अत्यंत सूक्ष्म विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। इससे पहले इतनी बारीकी के साथ इन संरचनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं हो पाया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन चित्रों से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की जटिल संरचना और उसके व्यवहार के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई है। सौर तूफान पृथ्वी के उपग्रहों, संचार प्रणालियों, विद्युत ग्रिड और अंतरिक्ष अभियानों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सूर्य की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझना वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए अवलोकनों से भविष्य में सौर गतिविधियों के पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने में भी सहायता मिलने की संभावना जताई गई है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इन उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों के विश्लेषण से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा प्रवाह और प्लाज्मा की गतिशीलता से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। वैज्ञानिक अब इन आंकड़ों के आधार पर आगे के अध्ययन में जुटे हैं, ताकि सौर तूफानों की प्रक्रिया और उनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को अधिक गहराई से समझा जा सके।

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ीं चुनौतियाँ

- विद्रोही गतिविधियों और सुरक्षा संकट के बीच कई क्षेत्रों में सरकार की पकड़ कमजोर होने के दावे

इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियां लगातार बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार दोनों प्रांतों में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में सरकार की पकड़ कमजोर हुई है, जिससे कानून-व्यवस्था और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) सहित विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कई इलाकों में विद्रोही संगठन सड़कों पर अवैध नाके लगाकर वाहनों की जांच और वसूली कर रहे हैं। पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों और ग्वादर बंदरगाह के विकास से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि बाहरी निवेश बढ़ने के बावजूद स्थानीय समुदाय रोजगार और आर्थिक अवसरों से वंचित हैं। इसी असंतोष को अलगाववादी संगठन अपने समर्थन के आधार के रूप में पेश करते रहे हैं। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अफगानिस्तान से लगी सीमा वाले क्षेत्रों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की गतिविधियों में वृद्धि की बात कही जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार कई सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी प्रभाव के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों के सामने लगातार चुनौती बनी हुई है। समय-समय पर सुरक्षा बलों और उग्रवादी संगठनों के बीच मुठभेड़ों की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों का असर शिक्षा, परिवहन और सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से विद्यालयों और अन्य संस्थानों का संचालन प्रभावित होने की बात कही गई है। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों प्रांतों में स्थिरता बहाल करना पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए सुरक्षा उपायों के साथ स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाली और विकास संबंधी प्रयास भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

सीमा क्षेत्रों के लिए 2715 लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदेगी भारतीय सेना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात सैनिकों तक रसद और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2,715 लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदने की तैयारी शुरू की है। यह सेना की अब तक की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक ड्रोन खरीद योजनाओं में शामिल माना जा रहा है।

इन ड्रोन का उपयोग गोला-बारूद, खाद्य सामग्री, दवाइयां, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक सैन्य सामग्री को दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात जवानों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इससे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रसद आपूर्ति की गति बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा। सेना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में कई बार मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पारंपरिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में लॉजिस्टिक ड्रोन सैनिकों तक कम समय में आवश्यक सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के अनुसार इन ड्रोन की मदद से आपातकालीन परिस्थितियों में भी आवश्यक सैन्य सामग्री तेजी से अग्रिम चौकियों तक पहुंचाई जा सकेगी। इससे संचालन क्षमता में वृद्धि होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना आसान होगा।

भारतीय सेना पिछले कुछ वर्षों में निगरानी, टोही और सामरिक अभियानों के साथ-साथ रसद प्रबंधन में भी ड्रोन तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ा रही है।

संसद में सरकार ने बताया प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का खर्च

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए व्यय की जानकारी प्रस्तुत की। विदेश मंत्रालय की ओर से लिखित उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2026 के दौरान प्रधानमंत्री की विभिन्न विदेश यात्राओं पर निर्धारित मदों के अनुसार खर्च किया गया।

सरकार ने कहा कि इन यात्राओं का उद्देश्य भारत के रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हितों को आगे बढ़ाना रहा है। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इन दौरों से भारत के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने और विभिन्न देशों के साथ सहयोग के नए अवसर विकसित करने में मदद मिली। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश यात्राओं पर होने वाले व्यय में विमान संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, आवास, स्थानीय परिवहन तथा अन्य आधिकारिक व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। सभी खर्च निर्धारित सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किए जाते हैं। विदेश यात्राएं केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होतीं, बल्कि इनके माध्यम से निवेश, व्यापारिक समझौते होते हैं।

लालच

युद्ध के बीच फर्जी विवाह के मामलों ने बढ़ाई चिंता, अस्पताल और सैन्य तंत्र पर भी उठे सवाल

रूस में सैनिकों के मुआवजे के लिए संदिग्ध शादियों के आरोप

मॉस्को, एजेंसी: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में सैनिकों की मौत पर मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर संदिग्ध शादियों के मामले चर्चा में हैं।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ महिलाओं पर आरोप है कि वे युद्ध पर जाने वाले अथवा घायल सैनिकों से जल्दबाजी में विवाह करती हैं और उनकी मृत्यु के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे पर दावा करती हैं। हालांकि ऐसे मामलों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है, लेकिन कई प्रकरण अदालतों तक पहुंच चुके हैं।

रूसी मीडिया में ऐसी महिलाओं को 'ब्लैक विडो' कहा जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ मामलों में सैनिकों ने मोर्चे पर जाने से ठीक पहले या अस्पताल में उपचार के दौरान विवाह किया। इन घटनाओं में अस्पताल और सेना के कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सबसे चर्चित मामलों में एक सैन्य अस्पताल की नर्स पर उपचाराधीन पांच घायल सैनिकों से अलग-अलग समय पर विवाह करने का आरोप लगा। आरोप है कि वह सैनिकों की मृत्यु के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे की लाभार्थी बनना चाहती थी। मामला सामने आने के बाद संबंधित नर्स को सेवा से हटा दिया गया।

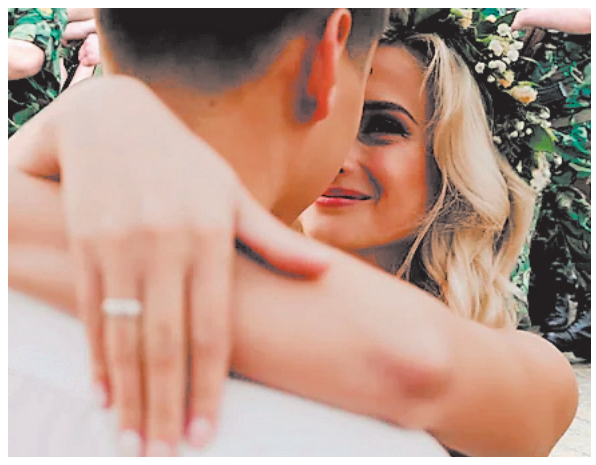

एक अन्य मामले में सेंट पीटर्सबर्ग की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने युद्ध पर जाने से दो दिन पहले एक ऐसी महिला से विवाह किया, जिससे परिवार परिचित नहीं था। सैनिक की मृत्यु के बाद कानूनी पत्नी होने के कारण मुआवजे का अधिकार उसी महिला को मिल गया। परिवार ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी।

रूस में युद्ध में मारे गए सैनिक के परिवार को सरकार की ओर से लाखों रूबल की आर्थिक सहायता दी जाती है। आरोप है कि इसी मुआवजे के लालच में कुछ लोग अकेले, बुजुर्ग या कमजोर सैनिकों को विवाह के लिए निशाना बनाते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद सरकार ने सैनिकों के लिए विवाह प्रक्रिया को सरल बनाया था, ताकि उनके परिवारों को आवश्यक कानूनी और आर्थिक सहायता शीघ्र मिल सके। अब इसी व्यवस्था के दुरुपयोग के आरोप सामने आ रहे हैं।

रूसी सांसदों ने ऐसे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध मामलों की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।